



तालबान प्रतनिधि मंडल का पाकस्तान दौरा

प्रलिमिंस के लिये:

अमेरिका और तालबान शांति समझौता

मेन्स के लिये:

क्षेत्रीय शांति पर तालबान शांति समझौते का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तालबान के दोहा स्थिति राजनीतिक कार्यालय से एक उच्च-स्तरीय प्रतनिधि मंडल अफगानस्तान शांति प्रक्रिया पर पाकस्तानी नेतृत्व से चर्चा के लिये पाकस्तान पहुँचा।

प्रमुख बंदि:

- तालबान के राजनीतिक प्रमुख 'मुल्ला अब्दुल गनी बरादर' (Mullah Abdul Ghani Baradar) के नेतृत्व में यह उच्च-स्तरीय प्रतनिधि मंडल पाकस्तानी वंदिश मंत्रालय के निर्मिंतरण पर इस्लामाबाद पहुँचा है।
- पाकस्तानी वंदिश मंत्री के अनुसार, पाकस्तान अफगान मुददे पर एक मध्यस्थ/सहायक की भूमिका नभिरा है, जसके कारण अमेरिका और तालबान के बीच यह समझौता सुनश्चिति हो सका है तथा अब इसका भवषिय अफगानस्तान प्रशासन के नरिणय पर नरिभर करता है।
- यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों तरफ से कैदियों के हस्तांतरण के वंदिदति प्रावधान के बीच [अफगान शांति वार्ता](#) पुनः स्थगति हो गई है।
- गौरतलब है कि पिछले 10 माह में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की यह दूसरी पाकस्तान यात्रा है।
- पाकस्तानी वंदिशमंत्रि के अनुसार, अफगानस्तान की शांति प्रक्रिया में अगला तार्ककिक कदम अंतर-अफगान वार्ता होगी जसि शीघ्र ही शुरू कथिा जाना चाहथि।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2001 में अफगानस्तान में अमेरिकी सेना के प्रवेश के लगभग 2 दशक बाद फरवरी 2020 में अमेरिका और तालबान के बीच एक [शांति समझौते](#) पर हस्ताक्षर कथिा गए थे।
- इस समझौते के तहत अमेरिका अगले 14 महीनों में अफगानस्तान से अपने सभी सैनिक वापस बुलाने पर सहमत हुआ था।
- फरवरी 2020 के समझौते के तहत अफगानस्तान सरकार और तालबान के बीच कैदियों की रंहिाई पर भी एक समझौता हुआ।
- इसके तहत अफगानस्तान सरकार द्वारा देश की जेलों में बंद लगभग 5,000 तालबानी कैदियों और तालबान द्वारा पकड़े गए लगभग 1000 सरकारी कर्मचारियों तथा सैन्य कर्मथियों को 'अंतर-अफगान वार्ता' (Intra-Afghan Negotiations) के पहले रंहिा करने पर सहमति वियकृत की गई थी।

शांति प्रक्रिया के बाधति होने का कारण:

- वर्तमान में तालबान द्वारा लगभग 1,000 सरकारी कर्मचारियों और सैन्य कर्मथियों तथा अफगानस्तान सरकार द्वारा लगभग 4,680 चरमपंथियों को रंहिा कथिा जा चुका है।
- हालाँकि अफगानस्तान सरकार ने हाल ही में कुछ बचे हुए (लगभग 300) तालबानी कैदियों को रंहिा करने मना कर दथिा है। अफगानस्तान सरकार के अनुसार, ये कैदी कई गंभीर हमलों से संबंधति हैं।

पाकस्तान का हस्तक्षेप :

- अफगानिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान पर तालिबान को आश्रय देने और फंडिंग उपलब्ध कराने का आरोप लगाया जाता रहा है।
- गौरतलब है कि 1990 के दशक के दौरान अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को मान्यता देने वाले देशों में से पाकिस्तान भी एक था।
- यदि अफगानिस्तान में तालिबान की स्थिति मजबूत होती है तो इससे अफगानिस्तान की राजनीति में पाकिस्तान का हस्तक्षेप बढ़ेगा।

भारत पर प्रभाव :

- भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान में वदेशी हस्तक्षेप से मुक्त एक लोकतांत्रिक सरकार का समर्थक रहा है।
- अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हस्तक्षेप का लाभ पाकिस्तान कश्मीर में चरमपंथ को बढ़ावा देने के लिये कर सकता है।

आगे की राह:

- अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को पूरी तरह से हटाए जाने से क्षेत्र में एक बार पुनः अस्थिरता बढ़ सकती है।
- भारत को क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिये तालिबान से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने पर विचार करना चाहिये।

स्रोत: द हिंदू